Shri S. M. Banerjee has already referred to it, and, therefore, I need not mention names of those great dignitaries. Would the hon. Minister be good enough to say specifically one thing? In regard to these allegations that have been made, this is not the first time that these allegations have been made. This is not the first time that these names have been mentioned in this House; several times in the past they have been mentioned, and the Ministers concerned also had something to say in this House.

Would the hon. Minister be good ehough to say whether that particular CBI report was placed before the Sarkar Committee and whether also, after the CBI concludes its report on the query made by the Reserve Bank of India, that report would be placed before that commission and whether both these reports or their summaries would be placed on the Table of the House?

SHRI P. C. SETHI: I have already stated that with regard to the foreign exchange infringement, the matter is being investigated by the CBI. With regard to the imports that this party has done in excess of what they were allowed to do, about two or three cases relating to these imports are under inquiry by the CBI.

As regards the other question about the other subjects on which the CBI has inquired into the working of this firm, I shall certainly collect the information and place it on the Table of the House.

श्री रवि राय: इस रिपोर्ट में दो डिगनेटरीज़ के नाम हैं या नहीं?

SHRI P. C. SETHI: Which report?

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†696. **श्री ओंकार सिंह**:
श्री जगन्नाथराव जोशी:
श्री राम गोपाल शालवाले:

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हाल ही में केवल मध्य प्रदेश के ही इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण भूमिगत तारों के मामले में एक लाख रुपये तक की हानी हुई है और अपेक्षित दस्तावेजों के समय पर बम्बई पत्तन में न पहुंचने के कारण हानि के रूप में एक लाख रुपये की हानि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी लापरवाही के कारण 30,000 रुपये के मूल्य की 4,700 लिटर वार्निश भी नष्ट हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अलीअहमद): (क) से (घ): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल द्वारा पिछले 10 वर्षों में लगभग 500 स्नातक अप्रैंटिस इंजीनियरों की अखिल भारत के आधार पर भर्ती की गई थी। तथापि, हाल ही में केवल मध्य प्रदेश के आवेदकों में से तथा कम्पनी के निम्न पदों से पदोन्नति के द्वारा 31 इंजीनियरों के एक दल का चयन किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ कि केवल इसी राज्य से कई सौ अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों ने आवेदन दिये थे और आवश्यकता कम व्यक्तियों की होने के कारण व्यवस्थापकों ने इन्हीं उम्मीदवारों तक चयन सीमित रखा। व्यवस्थापकों के इस निर्णय का सरकार ने अनुमोदन नहीं किया और व्यवस्थापकों ने अब इसकी पुष्टि कर दी है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायगी।

(ख) दिसम्बर, 1960 में कम्पनी ने 594,798 रु० के मूल्य के ज़मीन के नीचे बिछाये जाने वाले केबलों के लिये आर्डर दिया था। अगस्त, 1961 में 55,088 रु० के मूल्य के केबलों की पूर्ति हो जाने के बाद शेष के लिये आर्डर रद्द कर दिया गया था क्योंकि जो माल दिया गया वह सन्तोषजनक नहीं समझा गया और 648.600 रु० की लागत के

केबलों के लिये एक दूसरी कम्पनी को एक नया आर्डर दे दिया गया था। तुरंत आवश्यकता के कारण ऊंची दर पर केबल खरीदने से 108,890 रु० अधिक खर्च करने पड़े।

कम्पनी ने 94,028.48 रु० विलम्ब शुल्क दिया है। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से कहा गया है कि इसमें से 25,698.96 रु० का दायित्व वह बर्दाश्त करें क्योंकि विलम्ब शुल्क का यह अंश उनके कार्यालय के जरिये कागजात भेजने में विलम्ब का द्योतक है।

(ग) देश में साधनों से 4,700 लिटर 'थर्मो हार्योनिंग वार्निश' खरीदी गई थी। खरीदने के समय उसकी किस्म सन्तोषजनक थी किन्तु उपयोग में देरी होने से और वार्निश की अवधि समाप्त हो गई और वह इस्तेमाल नहीं की जा सकी। फलस्वरुप लगभग, 30,000 रु० की हानि हुई।

(घ) इंजीनियरों की नियुक्त के बारे में व्यवस्थापकों के निर्णय का सरकार ने अनुमोदन नहीं किया है और व्यवस्थापकों ने अब इसकी पुष्टि कर दी है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई की जायगी।

(2) ऊंची कीमतों पर केबलों की खरीद के संबंध में व्यवस्थापकों ने जांच का आदेश दे दिया है जिससे उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके और जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है। जहां तक विलम्ब शुल्क का संबंध है, कम्पनी से इसकी जांच करने के लिए कहा गया है कि इतना अधिक विलम्ब शुल्क क्यों हुआ और इस बात का सुनिश्चय करने के हेतु कारगर कारवाई करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में इस प्रकार का विलम्ब-शुल्क फिर न लगने पाये।

(3) वार्निश का समय से इस्तेमाल न किये जाने के प्रश्न की जांच पड़ताल करने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों की एक विभागीय समिति नियुक्त की गई थी। समिति का यह मत था कि पेंट और वार्निश की कुछ मदों के लिए अधिक मांग-पत्र (इन्डैंट) दिये गए और ऐसा क्रय प्रक्रियाओं वस्तु सूची नियंत्रण तथा परियोजना के प्रारम्भिक चरणों में अपर्याप्त अनुभव के कारण हुआ। इसके अलावा अधिक उत्पादन के लक्ष्य का अनुमान लगाया था जिसके फलस्वरूप यह माल अधिक परिमाण में खरीदा गया। समिति द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझाये गये उपाय लागू कर दिये गये हैं।

श्री ओंकार सिंह: क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की पौलिसी के मातहत तीसरी श्रेणी तथा पांचवी श्रेणी के अलावा अन्य सभी कमचारी भारतीय स्तर पर रखे जाने चाहियें। लेकिन वहां पर इस पालिसी के बजाय प्रान्तीय स्तर पर लोगों को रखा गया है—इस का कारण क्या है? यदि इस में भारत सरकार के नियम का उलंघन हुआ है तो भविष्य में इस को बचाने के लिये सरकार ने क्या किया है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: जैसा कि जवाब में बतलाया गया है अभी तक 500 इन्जीनियर्स रखे गये हैं जिनको आल-इण्डिया बेसिज पर लिया गया था। लेकिन अभी हाल में 31 इन्जीनियर्स और लिये गये हैं, जिनको प्रमोशन के बेसिज पर लिया गया है या मध्य प्रदेश से लिया गया है। मध्य प्रदेश से इस लिये लिया गया था कि वहां पर बहुत सारे इन्जीनियर्स अन-एम्पलायड थे। गवर्नमेन्ट ने उन को लिखा है कि ऐसी एप्वाइन्टमेन्ट्स प्राविन्स के बेसिज पर नहीं होनी चाहिये, बल्कि आल इण्डिया बेसिज पर होनी चाहियें। कम्पनी ने इस बात को मान लिया है कि आइन्दा वह इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी वह रेक्रटमेन्ट करेंगे—आल इण्डिया बेसिज पर करेंगे।

श्री ओंकार सिंह: वहां पर जो हानि हुई है, उस हानि की जांच और उस से बचने के लिये क्या सरकार कोई कमेटी मुकर्रिर करने को तैयार है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की हानि और त्रुटियों से बचा जा सके तथा वह रिपोर्ट सदन के सामने पेश हो?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: जहां तक केबल्ज खरीदने का ताल्लक है—ज्यादा

कीमत पर खरीदे गये और एक फर्म से न लेकर दूसरी फर्म से लिये गये—हम ने उन से कहा है कि कम्पनी इस में जांच करें और रेस्पोन्सिबिल्टी फिक्स करे कि किस की वजह से यह सब हुआ है। जब उसकी रिपोर्ट आयेगी तब इस के बारे में मालूम होगा। यह मामला एस्टीमेट्स कमेटी में भी जानेवाला है, उनकी रिपोर्ट आने पर जो कार्यवाही जरूरी समझेंगे करेंगे।

श्री राम गोपाल शालबाले: भूमिगत तारों में जो एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है—उस नुकसान में किन लोगों का हाथ था। क्या यह सच है कि इस बड़े कारखाने में कुछ पाकिस्तानी तत्व काम करते हैं और उन पाकिस्तानी तत्वों के कारण इस प्रकार का नुकसान हुआ है? यदि यह सच है, तो इतने महत्वपूर्ण कारखाने में इस प्रकार के जो लोग काम करते हैं, उन की जांच के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है, अगर नहीं की है, तो क्या अब करने का इरादा है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: मैंने पहले सवाल का जवाब दे दिया है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि नुकसान के लिए कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं। उसकी इंक्वायरी होगी और एस्टिमेटस कमेटी की भी रिपोर्ट आयेगी, फिर गौर किया जायेगा। इस बात की इतला मेरे पास नहीं है कि नुकसान किसी पाकिस्तानी की वजह से हुआ है या कोई पाकिस्तानी इस कारखाने में काम कर रहा है।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो इंजीनियर्स हेवी एलेक्ट्रिकल्स, भोपाल की सर्विस में लिए गए हैं वे उन इंजीनियर्स में से थे जो अन्तर्प्रान्तीय चमोली योजना का काम पूरा हो जाने के कारण बेकार हुए हैं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: आजकल बहुत सारे इंजीनियर्स जिन्होंने कि हाल में पास किया है उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है और कुछ पुराने भी बेकार होंगे। दोनों सूरतों में हो सकता है कि बेकार हों।

राजनैतिक दलों को धन दिया जाना

*697. **श्री बृज भूषण लाल**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी कम्पनियों में 25 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी लगी हुई है;

(ख) 1966–67 में इन कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को कितनी-कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) राजनीतिक दलों को दी गई इस राशि में कितनी विदेशी पूंजी शामिलहै;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राजनैतिक दलों को धन दिया जाना

*704. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**:
श्री जि० ब० सिंह:
श्री राम सिंह अयरवाल:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार अथवा ऐसी संस्थाओं के 25 प्रतिशत अंश हैं, जिनमें सरकारी पूंजी लगी हुई हैं;

(ख) 1966–67 में उक्त कम्पनियों ने राजनीतिक दलों को कितनी धनराशि दान में दी; और

(ग) उक्त धनराशि में सरकारी तथा सार्वजनिक धनराशि का औसत कितना है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI): (a) to (c). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

SHRI S. M. BANERJEE: Previously the notice was only 10 days; now it is 21. You know how questions come up. They are all by ballot, and